

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक २० सितम्बर, 2011

विषय:-जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत नैनीताल सीवरेज योजना हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: भा०स०-145/IV-श०वि०-09-18 (एन0यू0आर0एम0)/09टी०सी०, दिनांक 20 जुलाई, 2009 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत नैनीताल सीवरेज योजना हेतु ₹ 1960.00 लाख की डी०पी०आर० के सापेक्ष प्रथम चरण के लिए केन्द्रांश ₹ 392.50 लाख तथा राज्यांश ₹ 9.8. 13 लाख इस प्रकार कुल ₹ 490.63 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार की केन्द्रीय संस्तुति एवं मानिटरिंग कमेटी की 98वीं बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 59(1)/PF-I/2011-587, दिनांक 01-09-2011 द्वारा उक्त योजना हेतु द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 235.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नैनीताल सीवरेज योजना हेतु उक्त केन्द्रांश ₹ 235.20 लाख तथा इस केन्द्रांश की धनराशि के सापेक्ष देय 20 प्रतिशत राज्यांश ₹ 58.80 लाख की धनराशि सहित कुल ₹ 294.00 लाख (₹ दो करोड़ चौरानबे लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि ₹ 294.00 लाख (₹ दो करोड़ चौरानबे लाख मात्र) आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. भा०स०-145/IV-श०वि०-09-18 (एन0यू0आर0एम0)/08, दिनांक 13 जुलाई, 2009 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
4. जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे०एन०एन०य०आर०एम० योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के पृथक-पृथक प्रस्ताव तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये, और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
8. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
9. कार्य पूर्ण होने पर इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार एवं भारत सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।
10. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैटर्न से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31-3-2012 तक पूर्ण उपयोग कर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भारत सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा।

3— उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13, लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना-05-नेशनल अरबन रिनियूअल मिशन-20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता की मद के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०-524/XXVII(2)/2011, दिनांक 15 सितम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव।